सेवा भाव से योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें : भजनलाल शर्मा

- राज्य में 90 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए 1500 करोड़
- मुख्यमंत्री ने की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के वंचित वर्ग के कल्याण हेतु समर्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्ग को मिलना सुनिश्चित हो इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सेवाभाव से कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे तथा अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न ले पाए, क्योंकि इससे पात्र व्यक्ति के हितों पर कुठाराघात होता है। शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता तय कर चरणबद्ध रूप से किया जाए। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पत्थर तोड़ने एवं पीसने के कार्य वाले स्थानों एवं खदानों पर निर्धारित गाईडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएं ताकि सिलिकोसिस रोग पर नियंत्रण किया जा सके।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई निर्णय किए हैं। राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड की राशि को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये किया गया है। राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को देय मेस भत्ता भी 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। शर्मा ने कहा कि आश्रय से वंचित घूमंतू समुदाय के लोगों के लिए घूमंतू आवासीय योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के दिव्यांग नागरिकों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, 2 हजार युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने के लिए स्कूटी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ कर 5 हजार रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार लगभग 90 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की पात्रता व उनसे जुड़े रिकॉर्ड का नियमित रूप से सत्यापन करें और इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे पेंशनर्स की मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कर संबंधित कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जाए।

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, शासन सचिव वित्त (व्यय) नवीन जैन, आयुक्त निशक्तजन एच. गुईटे, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता बचनेश अग्रवाल सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट व ब्रज चौरासी यात्रा पर प्रस्तुतिकरण

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के समक्ष सोमवार को पर्यटन भवन में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत तथा पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की उपस्थिति में ''महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट'' और ''ब्रज चौरासी यात्रा की'' कॉन्सेप्ट प्लान और पार्लियामेंट्री रिपोर्ट बनाने के लिए प्राप्त निविदाओं का कन्सलटेन्टस व आर्किटेक्ट्स ने प्रस्तुतिकरण दिया।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के समक्ष सोमवार को पर्यटन भवन में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत तथा पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की उपस्थिति में ''महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट'' और ''ब्रज चौरासी यात्रा की'' कॉन्सेप्ट प्लान और पार्लियामेंट्री रिपोर्ट बनाने के लिए प्राप्त निविदाओं का कन्सलटेन्टस व आर्किटेक्ट्स ने प्रस्तुतिकरण दिया।

प्रस्तुतिकरण में दोनों जगहों का विकास करने तथा यहां आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं देने पर बिंदुवार चर्चा की गई। दिया कुमारी ने प्रस्तुतिकरण के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज विभिन्न एजेंसियो की ओर से प्रस्तुतिकरण दिए गए हैं। इस आधार पर बिंदुवार नियोजित रूप से योजना बनाकर काम किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन विभाग की 145 करोड़ की दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी पर पत्रकारों के समक्ष केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का आभार जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि जयपुर में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित करने को लक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की योजना के क्रियान्वयन का काम चल रहा है।

नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जयपुर फुट की कार्य प्रणाली जानी

जी-20 में भारत सरकार के निजी प्रतिनिधि और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने जयपुर फुट की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया।

जयपुर। जी-20 में भारत सरकार के निजी प्रतिनिधि और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने जयपुर फुट की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया।

जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस. एस.) के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता, सचिव भूपेन्द्र राज मेहता तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एस. बिस्सा ने अमिताभ कान्त का स्वागत किया और जयपुर फुट की निर्माण विधि की जानकारी दी। अमिताभ कान्त ने कहा कि बी.एम.वी.एस.एस. निस्वार्थ भाव से विकलांगों को सेवा कर रही है और यह विश्व में अपनी तरह की अद्वितीय सस्था है, जिसने सारे भारत और विश्व भर में जयपुर फुट प्रचलित कर विकलांगों की सेवा की। उन्होंने कहा कि डी.आर. मेहता ने आई. ए.एस. अधिकारी रहते हुए न सिर्फ बी.एम.वी.एस.एस. की स्थापना कर एक अनुकरणीय संस्था बनाने में योगदान दिया बल्कि इस विश्व भर में ख्याति भी दिलाई।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि जयपुर फुट जैसे गुणवत्ता वाले उपकरण और अधिक प्रचलित हों और अधिक से अधिक विकलांगों द्वारा अपनाये जाये। अमिताभ कान्त ने दस विकलांगों के पुर्नवास और उन्हें जयपुर फुट लगाने के लिए योगदान दिया।

समिट में न्यूनतम होगा प्लास्टिक का उपयोग

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने सोमवार को पांचवा संकल्प लेते हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने का निश्चय किया है।

प्रधानमंत्री विशाल जनसभा में ई.आर.सी.पी. परियोजना का शिलान्यास करेंगे : मदन राठौड़

- परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेशभर से करीबन तीन लाख लोगों की उपस्थिति रहेगी

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ यूसीसी, कृषक मित्र भाजपा सरकार, अवैध धर्मोन्तरण और राजस्थान में भाजपा सरकार के कार्यों पर चर्चा की। राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राजस्थान में भाजपा की सरकार लगातार जनहितैषी कार्यों को कर रही है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा जहां समान नागरिकता कानून का समर्थन किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा ईआरसीपी योजना को मूर्त रूप देकर लाखों किसानों के लिए सिंचाई साथ आमजन के लिए पेयजल की समस्या का समाधान करने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। ईआरसीपी योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर के दादिया में किया जाएगा।

राठौड़ ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना का प्रारूप 2015-16 में तैयार किया गया, इसके बाद प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अटकाने का काम किया हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता में आने के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस जीवन दायनी परियोजना पर कार्य शुरू किया और अब इसका शिलान्यास होगा। परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेशभर से करीबन तीन लाख लोगों की उपस्थिति रहेगी। इससे जहां पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा, वहीं सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त जल भी मिलेगा। राठौड़ ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष को सकारात्मक कार्यों में अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए। हालांकि विपक्ष का कार्य आरोप प्रत्यारोप लगाना ही रह गया है। भाजपा ने प्रदेश की जनता के लिए ईआरसीपी, पीकेसी के साथ जवाई पुर्नभरण योजना पर भी कार्य शुरू किया। इसके साथ प्रदेश के बांध, नहरों के पुर्नभरण सहित अन्य विकास के कार्यों को प्राथमिकता से किया जा रहा है।

'मस्जिदों को मंदिर बता कर झूठे केस दायर किये जा रहे हैं'

- अजमेर दरगाह और संभल मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

जयपुर। राजस्थान के अजमेर और उत्तर प्रदेश के संभल मामले को लेकर आज मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी ने कहा कि धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने का घिनौना काम किया जा रहा है। देश के आपसी सद्भाव को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिदों को मंदिर बात कर अदालत में झूठे केस दायर किया जा रहे हैं। सर्वे के नाम पर मस्जिदों के स्टेटस को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर होने के बहाने सर्वे करा कर देश का माहौल खराब किया गया। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाकर मुस्लिम को जमीनों को हड़पना चाहती है। संबल मामले में जिस तरह से मस्जिद को बचाने अपने हक की आवाज को उठाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ इस दौरान पांच युवाओं की हत्या कर दी गई।

उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब की दरगाह इंसानियत और भाईचारे का संदेश देती है, और ऐसे पवित्र स्थलों पर विवाद पैदा करना गलत है। अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह को धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। उन्होंने ऐसी याचिकाओं को देश का माहौल खराब करने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश बताया। ऐसी याचिकाओं को खारिज किया जाए ताकि देश की गंगा-जमुनी तहज़ीब और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे।

मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करेंगे कि जिस तरीके से निचली अदालत सर्वे को लेकर आदेश दे रही है उनको लेकर गाइडलाइन जारी की जाए। संभल मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए। जो युवा संभल मामले में मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए साथ ही जिन पुलिस कर्मियों ने उनको मारा है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए।

नाजीमुद्दीन, अध्यक्ष जमाते इस्लामी हिंद, हाफिज मंजूर, जमीयत उलेमा हिंद, शहाबुद्दीन खान, उपाध्यक्ष, एडवोकेट सहादत अली मौजूद थे।

पुलिस अधिकारी बताए बिना अपराध क्यों की गिरफ्तारी : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में सरकारी वकील को कहा है कि संबंधित पुलिस अधिकारी का शपथ पत्र पेश कर बताए कि अब अनुसंधान में आईपीसी की धारा 326 के तहत अपराध साबित नहीं हुआ और अन्य अपराध जमानती प्रकृति के हैं तो याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी क्यों किया गया। जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा शर्मा व सौरभ की याचिका पर दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डीके शर्मा ने अदालत को बताया कि सार्थक शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में पुलिस ने गलत तरीके से उसके साले याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सार्थक के परिजनों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए पुलिस को दबाव में लेकर याचिकाकर्ता को झूठे मामले में गिरफ्तार करवा दिया।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति सार्थक शर्मा ने उसके साथ मारपीट और अभद्रता कर उसे घर से निकाल दिया था। इस पर उसने अपने भाई सौरभ को बुलाया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके खिलाफ ही 8 दिसंबर, 2023 को जवाहर नगर थाने में मारपीट व सशस्त्र हमला सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करा दिया। वहीं पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जबकि मामले में धारा 326 के तहत अपराध साबित नहीं हुआ और अन्य धाराएं जमानती अपराधों से जुडी हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का शपथ पत्र पेश करने को कहा है।

बजरी की अवैध सप्लाई के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

- अगर प्रशासन ने रोक नहीं लगाई तो सप्लाई बंद कर देंगे : नवीन शर्मा

जयपुर। प्रदेश में बजरी की बढती दरों के लिए राज्य सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। शहर में बजरी मंडियों में अवैध बजरी सप्लाई को लेकर व्यापारी लामबंद हो गए हैं।

नदी क्षेत्र में वैध बजरी खनन के लिए समय पर लीज जारी नहीं की जा रही है जिसके कारण अवैध बजरी खनन को बढावा मिल रहा है। यह बात ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर वैलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने आरोप लगाया कि अवैध बजरी खनन को बढावा देने के लिए पुलिस प्रशासन वैध रवन्ना के साथ बजरी परिवहन करने वाले ट्रक ऑपरेटर्स को परेशान कर रही है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध बजरी खनन व परिवहन बंद नहीं किए जाने पर सभी ट्रक ऑपरेटर्स बजरी परिवहन बंद कर देंगे। नवीन शर्मा ने कहा कि अवैध बजरी परिवहन को बंद करवाने के लिए लाइसेंस धारक व्यापारियों ने इस संबंध में आज खान विभाग के अधिकारियों को पत्र देकर इसे रुकवाने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर वैध बजरी खनन क्षेत्रों से खनन बंद करने और सप्लाई रोकने की चेतावनी दी है। टोंक, सवाई माधोपुर एरिया में कई ब्लॉक में अवैध बजरी का खनन हो रहा है। उन खनन एरिया के आसपास रिमोट एरिया (गांवों में) बजरी के अवैध स्टॉक बनाए जा रहे हैं। इन स्टॉक में अवैध तरीके से खनन करके बजरी एकत्रित किया जा रहा है। उसे जयपुर शहर और जिले के आसपास के कस्बों और गांवों में सप्लाई किया जा रहा है। इससे लाइसेंस धारी बजरी व्यापारियों को न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकार को भी हर रोज लाखों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है।

शर्मा ने बताया कि यूनियन ने खान विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर इन अवैध स्टॉक करने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की है। इसके साथ ही हमने प्रशासन ने जल्द ही दूसरे वैध स्टॉक (टोंक, सवाई माधोपुर एरिया में) को भी शुरू की मांग की है। अगर सरकार 10-15 दिवस में इन अवैध बजरी परिवहन और स्टॉक करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं करती तो मजबूरन सभी ट्रक ऑपरेटर्स जो वैध लीज से बजरी लाकर सप्लाई कर रहे है उसे बंद करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने अनुशासनहीन नौ कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी

जयपुर। राज्य सरकार राजकीय कार्यालयों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस विभाग के 9 अनुशासनहीन कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृति देने का निर्णय किया है।

यह निर्णय राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 53 (1) के प्रावधान के तहत पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित रिव्यू कमेटी एवं प्रशासनिक सुधार की आज्ञानुसार गठित उच्च स्तरीय स्थायी समिति की अनुशंसा पर किया गया है। इन कार्मिकों ने घोर लापरवाही करते हुए अनुशासनहीनता एवं अनियमितताएं की थी, जिसके लिए पूर्व में उन्हें कई बार दंडित भी किया गया था।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस का बेहतरीन मॉडल स्थापित करने के लिए राज्य सरकार लापरवाह एवं अनुशासनहीन कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही, कर्मठ और ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए भी दृढ़ता से कार्य कर रही है। हम आमजन को राजकीय कार्यालयों में उत्तम सेवाएं देने के लिए संकल्पित है।

भजनलाल सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करें : डॉ. प्रेमचंद बैरवा

- उपलब्धियों के शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया और प्रमुख चौराहों पर डिजिटल एलईडी पैनल पर प्रदर्शित होंगे

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की।

जयपुर (कासं)। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आयुर्वेद विभाग की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, योजनाओं का आमजन तक उचित प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने प्रत्येक विभाग को अपनी एक वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए लघु वृत्तिचत्र (डॉक्यूमेंट्री) का निर्माण करने और इस वृत्तिचत्र को विभागीय वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा प्रमुख चौराहों पर स्थापित डिजिटल एलईडी पैनलों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख स्थानों पर विशेष होर्डिंग्स लगाए जाएं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शिक्षा संकुलों के समीप, आयुर्वेद विभाग द्वारा चिकित्सालयों के निकट, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा परिवहन कार्यालयों के आस-पास तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रमुख बस स्टैंड के समीप एवं विभागीय मुख्य भवनों पर होर्डिंग्स स्थापित किए जाएं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपनी एक वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए रंगीन सचित्र बुकलेट का मुद्रण एवं जन सामान्य तक वितरण सुनिश्चित करे ताकि अधिकतम जन-जन तक विभागीय उपलब्धियों की जानकारी पहुंच सके।

डॉ. बैरवा ने कहा कि विभागीय उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख समाचार पत्रों, ऑडियो एवं वीडियो फिल्म के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जाए।

बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अध्यक्ष शुभ्रा सिंह, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की शासन सचिव डॉ. आरूषी अजेय मलिक, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की आयुक्त एवं शासन सचिव शुचि त्यागी, रोडवेज प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा, मीडिया सलाहकार आनंद शर्मा सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद थे।

ट्रक चालकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कैबिन में लगाए जाएंगे ए.सी. : मदन राठौड़

- 'जून 2025 के बाद निर्मित एन-2 और एन-3 श्रेणी के ट्रकों के कैबिन में चालकों की सुविधा के लिए शुरू होगी वातानुकूलन प्रणाली'
- राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दी जानकारी

जयपुर। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि अब माल वाहनों में चालकों की सुविधा के लिए भी नए वाहनों में चालक कैबिन एसी युक्त बनाने की पहल की जा रही है। इतना ही नहीं राजधानी जयपुर से अजमेर की ओर जा रहे नेशनल हाइवे 8 पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए इसे 8 लेन का बनाया जाएगा। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है। राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में 6 एवं 8 लेन नेशनल हाइवे और ट्रक चालकों की सुविधा में विस्तार संबंधी सवाल राज्यसभा में लगाया गया था, इसके जवाब में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने यह जानकारी दी।

राठौड़ बताया कि केंद्र सरकार देश में निजी ट्रक वाहनों में चालकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के साथ चालक की थकान की समस्या का समाधान करने की दिशा में भी कदम बढाया है। राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जून 2025 के बाद निर्मित एन-2 और एन-3 श्रेणी के मालवाहक ट्रक के कैबिन में चालकों की सुविधा के लिए वातानुकूलन प्रणाली लगाई जाएगी। इसके लिए इन श्रेणी के वाहनों में चेसिस निर्माताओं द्वारा निर्धारित आईएस के अनुसार वातानुकूलन प्रणाली के लिए एक अनुमोदित किट की आपूर्ति भी की जाएगी, जिससे बॉडी तैयार करने वालों को किट लगाने की सुविधा हो सके। इससे ट्रक चालकों के केबिन में वातानुकूलित सुविधा शुरू हो जाएगी।